सुविचार

खुद का अपमान कराके जीने से तो अच्छा मर जाना है क्योंकि प्राणों के त्यागने से केवल एक ही बार कष्ट होता है पर अपमानित होकर जीवित रहने से आजीवन दु:ख होता है।

–चाणक्य

RNI No. RAJHIN/2001/05699

जनता की भावनाओं एवं आकांक्षाओं का एकमात्र समाचार-पत्र

www.hellosarkar.com www.hellosarkar.com www.hellosarkar.com www.hellosarkar.com www.hellosarkar.com

हैलो सरकार

पल-पल की टी.वी. एवं रेडियो खबरों के लिए लॉन ऑन करें- www.hellosarkar.com

हैलो सरकार समाचार पत्र में नियमित पाठक बनने, समाचार की प्रति मंगवाने व विज्ञापन देने हेतु सम्पर्क करें
फोन: 0141-2202717
मो: 9214203182
वाट्सप नं. 9928078717

वर्ष-25 | अंक-255 | दैनिक प्रभात संस्करण | जयपुर, मंगलवार 19 मई, 2026 | पृष्ठ-4 | मूल्य: 2.50

मुख्यमंत्री ने की जनसुनवाई-लोगों की समस्याओं का हुआ हाथोंहाथ समाधान

हैलो सरकार न्यूज

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर जनसुनवाई में प्रदेशभर से आई महिलाओं, विशेष योग्यजन, वरिष्ठ नागरिक एवं विभिन्न वर्गों के लोगों की समस्याओं को संवेदनशीलता से सुना। मुख्यमंत्री ने अनेक प्रकरणों में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देकर मौके पर ही परिवेदनाओं का समाधान कर परिवादियों को राहत दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसुनवाई आमजन और शासन के बीच विश्वास एवं संवाद का प्रभावशाली माध्यम है। हमारी सरकार सुशासन के उच्च मानकों पर कार्य करते हुए अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति को योजनाओं का लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनसुनवाई में आए सभी प्रकरणों के निस्तारण की समय-समय पर मॉनिटरिंग की जाए। अधिकारी ऐसी

पारदर्शी एवं प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करें, जिससे परिवादी को अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़े। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिवेदनाओं के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों पर सख्त कार्रवाई हो। जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याएं सुनकर परिवादियों से व्यक्तिगत संवाद भी किया। उन्होंने जनसुनवाई में बड़ी संख्या में आई महिलाओं, दिव्यांगों, बुजुर्गों सहित विभिन्न लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। आमजन अपनी परिवेदनाओं के हाथोंहाथ समाधान से बेहद संतुष्ट नजर आए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, श्रम, कृषि, गृह, राजस्व, जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल सहित विभिन्न विभागों की आमजन से जुड़ी परिवेदनाओं को सुना और उनके निस्तारण के निर्देश दिए।

ताराचंद को मिली इलेक्ट्रिक ट्राई साइकिल, विशाल को छात्रवृत्ति का लाभ- जनसुनवाई में नागौर से आए विशेष योग्यजन ताराचंद माली ने स्कूटी व इलेक्ट्रिक ट्राई साइकिल नहीं मिल पाने की अपनी पीड़ा मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। जिस पर मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाते हुए अधिकारियों को उन्हें शीघ्र स्कूटी व इलेक्ट्रिक ट्राई साइकिल देने के निर्देश दिए। इसी तरह, करौली के विशाल कुमार मीणा ने मुख्यमंत्री को बताया कि उन्हें उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है जिससे उन्हें आगे की पढ़ाई जारी रखने में समस्या आ रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उन्हें शीघ्र ही उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति दिलवाने के निर्देश दिए तथा उज्ज्वल भविष्य की कामना की। अपनी समस्याओं के इतने त्वरित समाधान से ताराचंद एवं विशाल बहुत खुश हुए और मुख्यमंत्री का आभार जताया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनप्रतिनिधिगण द्वारा लाए गए पोस्टरों का विमोचन भी किया। जनसुनवाई में बड़ी संख्या में संबंधित जनप्रतिनिधि और आमजन उपस्थित रहे।

पंचायत-निकाय चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट में सुनवाई टली, 26 मई को अगली सुनवाई

हैलो सरकार न्यूज

जयपुर। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव में हो रही देरी को लेकर राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल और जस्टिस अनिल कुमार उपमन की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 26 मई तय की है। दरअसल, पूर्व विधायक संयम लोढ़ा, गिर्राज सिंह देवंदा और अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सोमवार को सुनवाई प्रस्तावित थी। हालांकि, सरकार और राज्य चुनाव आयोग की ओर से चुनाव टालने संबंधी प्रार्थना पत्र पर फैसला पहले से सुरक्षित होने के कारण अदालत ने सुनवाई आगे बढ़ा दी।

इससे पहले पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयुक्त राजेश्वर सिंह को अवमानना नोटिस जारी किए थे। अदालत ने आयोग से सवाल किया था कि हाईकोर्ट के निर्देशों के बावजूद निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का कार्यक्रम तय समय सीमा से आगे कैसे जारी किया गया।

याचिकाकर्ता और पूर्व विधायक

राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह

संयम लोढ़ा ने अदालत में कहा था कि प्रदेश में पिछले डेढ़ साल से संवैधानिक संकट की स्थिति बनी हुई है और आमजन प्रशासकों की मनमानी से परेशान हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और चुनाव आयोग जानबूझकर चुनाव टाल रहे हैं, जो हाईकोर्ट के आदेश की सीधी अवमानना है।

यह भी पढ़ें- किडनी फेल होने से एक और मौत- कोटा में नहीं थम रहा प्रसूता की मौतों का सिलसिला; अब तक पांच हुई मौत

लोढ़ा ने यह भी कहा था कि चुनाव आयोग ने निकाय चुनाव के लिए 22 अप्रैल तक अंतिम मतदाता सूची जारी करने का कार्यक्रम तय किया था। ऐसे में यह स्पष्ट था कि हाईकोर्ट द्वारा तय 15 अप्रैल की समय सीमा में चुनाव कराना संभव नहीं होगा। इधर, पंचायत और निकाय चुनाव टालने को लेकर राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर 11 मई को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ में सुनवाई पूरी हो चुकी है। अदालत ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। सरकार ने अपने प्रार्थना पत्र में विभिन्न प्रशासनिक और आरक्षण संबंधी परिस्थितियों का हवाला देते हुए दिसंबर तक चुनाव टालने की मांग की है।

नीट-2026 परीक्षा पेपर लीक-कांग्रेस 21 मई को राजस्थान भाजपा मुख्यालय का घेराव करेगी

जयपुर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सोमवार को नीट-2026 परीक्षा पेपर लीक और इसमें भाजपा नेताओं की कथित संलिप्तता के विरोध में प्रदर्शन की घोषणा की। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता 21 मई को जयपुर स्थित भाजपा राज्य मुख्यालय का घेराव करेंगे। पार्टी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को भंग करने की मांग की है। मीडिया को संबोधित करते हुए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और मीडिया अध्यक्ष स्वर्णिम चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि नीट-2026 परीक्षा पेपर लीक देश भर के लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और इसके लिए केंद्र सरकार और एनटीए को प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया।

उन्होंने दावा किया कि जांच के दौरान कथित परीक्षा पेपर लीक में भाजपा नेताओं की संलिप्तता सामने आई है। चतुर्वेदी ने आगे आरोप लगाया कि नीट-2026 मामले में

शामिल आरोपियों ने पहले नीट-2025 पेपर खरीदा और लीक किया था, जबकि नीट-2024 परीक्षा का पेपर भी कथित तौर पर लीक किया गया था। कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वर्षों से परीक्षा में अनियमितताओं और प्रश्नपत्र लीक होने के आरोपों के बावजूद एनटीए के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आयोजित कई परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक हुए और परिणामस्वरूप परीक्षाएं रद्द की गईं, लेकिन दोषियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई।

कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि नीट-2026 प्रश्नपत्र लीक की जानकारी मिलने के बावजूद राजस्थान सरकार ने कार्रवाई में देरी की और पुलिस ने मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज नहीं की।

विरोध मार्च 21 मई को सुबह 10:00 बजे जयपुर स्थित राज्य कांग्रेस मुख्यालय से शुरू होगा। कांग्रेस कार्यकर्ता शहीद स्मारक होते हुए जुलूस निकालेंगे और भाजपा राज्य मुख्यालय पहुंचेंगे, जहां वे सुबह 11:00 बजे घेराव और प्रदर्शन करेंगे।

साइबर ठगी में फ्रीज बैंक खातों से मिलेगी राहत

राजस्थान पुलिस ने बताया GRM मॉड्यूल का आसान तरीका

जयपुर। साइबर धोखाधड़ी के मामलों में जांच के दौरान फ्रीज किए जाने वाले बैंक खातों से परेशान आमजन के लिए अब बड़ी राहत की खबर है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (द्ब4ष्ट) द्वारा विकसित त्रक्रू (तह्वद्द1ड्डठ्ठष्द्ध ऋद्गस्रद्गह्यद्बह्यद्ग स्र्द्गष्द्धड्डठ्ठद्बह्यद्व) मॉड्यूल अब ऐसे खाताधारकों के लिए प्रभावी और पारदर्शी समाधान बनकर उभरा है, जिनके बैंक खाते साइबर जांच के दौरान संदिग्ध ट्रांजेक्शन के कारण फ्रीज, लियन या होल्ड कर दिए जाते हैं। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस साइबर क्राइम श्री वीके सिंह ने बताया कि राज्य में साइबर अपराधों की रोकथाम और पीड़ितों को त्वरित राहत देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी दिशा में लागू किया गया GRM मॉड्यूल आमजन के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रहा है। पहले ऐसे मामलों में खाताधारकों को पुलिस, बैंक और विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और जवाबदेह तरीके से संचालित की जा रही है।

क्या है GRM मॉड्यूल?

GRM मॉड्यूल एक ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली है, जो नेशनल साइबर क्राईम रिर्पोटिंग पोर्टल (ह्रष्टक्रक्क) और सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिर्पोटिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम (ष्टस्नष्टस्नक्ररू) के अंतर्गत कार्य करती है। इसका उद्देश्य साइबर अपराध जांच के दौरान फ्रीज या लियन किए गए बैंक खातों की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक खाताधारकों को राहत उपलब्ध कराना है।

GRM प्रक्रिया के तहत खाताधारक सबसे पहले अपनी बैंक शाखा में जाकर खाते को अनफ्रीज करवाने या लियन हटाने के लिए आवेदन करता है। इसके बाद बैंक संबंधित व्यक्ति की चड्ढष्ट और ट्रांजेक्शन का सत्यापन करता है।

सत्यापन के बाद बैंक त्रक्रू पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर एक तह्वद्दद्ग1-ड्डठ्ठष्द्ध द्बष्ठ जनरेट करता है और मामला संबंधित थाना पुलिस जांच अधिकारी को भेजा जाता है।

पुलिस जांच अधिकारी ट्रांजेक्शन ट्रेल, संदिग्ध गतिविधियों और फ्रॉड इन्वॉल्वमेंट की जांच करता है। आवश्यकता पड़ने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खाताधारक का पक्ष भी सुना जाता है। जांच पूरी होने के बाद अधिकारी खाते को अनफ्रीज करने, लियन हटाने या शिकायत खारिज करने का निर्णय लेकर बैंक को सूचित करता है।

यदि थाना स्तर पर शिकायत खारिज होती है, तो खाताधारक जिला और राज्य स्तर के ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफीसर (त्रह्रह्र) के समक्ष अपील भी कर सकता है।

तीन स्तरों पर तय हुई जवाबदेही

त्रक्रू प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और बैंक दोनों स्तरों पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है।

पुलिस स्तर पर राज्य स्तर पर डीआईजी, जिला स्तर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/डीएसपी और थाना स्तर पर जांच अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है।

बैंक स्तर पर नेशनल नोडल ऑफिसर, स्टेट ग्रीवेंस ऑफिसर और ब्रांच ग्रीवेंस ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं।

राजस्थान पुलिस की अपील

राजस्थान पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने बैंक खाते, ओटीपी और निजी बैंकिंग जानकारी किसी के साथ साझा न करें। यदि किसी व्यक्ति का बैंक खाता अनपेक्षित रूप से फ्रीज हो जाता है और वह स्वयं को निर्दोष मानता है, तो तुरंत अपनी बैंक शाखा से संपर्क कर त्रक्रू प्रक्रिया शुरू करवाए। साइबर ठगी या संदिग्ध गतिविधि की स्थिति में तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन, साइबर पुलिस स्टेशन, साइबर क्राइम पोर्टल https://cybercrime.gov.in, साइबर हेल्पलाइन 1930 या साइबर हेल्पडेस्क नंबर 9256001930 / 9257510100 पर सूचना दे।

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया ट्रेन में सफर

1.85 करोड़ की साइबर ठगी मामले में सहआरोपी गिरफ्तार

हैलो सरकार न्यूज

जयपुर। डिजिटल अरेस्ट साइबर फ्रॉड के खिलाफ जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.85 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में एक और सहआरोपी को गिरफ्तार किया है। साइबर अपराधियों ने खुद को जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर महिला को डिजिटल अरेस्ट किया और डराकर 1.85 करोड़ रुपये ठग लिए थे। पुलिस ने करीब 500 किलोमीटर तक पीछा कर आरोपी को सवाईमाधोपुर जिले से गिरफ्तार किया है। पुलिस आयुक्त शरत कविराज और पुलिस उपायुक्त मुख्यालय शाहीन सी. के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त त्वरित अनुसंधान इकाई धन्ना राम के सुपरविजन में सहायक पुलिस आयुक्त साइबर थाना पदमदान चारण के निर्देशन में पुलिस निरीक्षक सुरेश सारण के नेतृत्व में गठित टीम ने यह कार्रवाई की।

घटनाक्रम के अनुसार साइबर पुलिस थाना में 23 फरवरी 2026 को महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि अज्ञात साइबर ठगों ने व्हाट्सएप कॉल कर खुद को जांच एजेंसी का अधिकारी बताया और उसके आधार कार्ड के अपराध में इस्तेमाल होने का भय दिखाया। इसके बाद महिला को लगातार निगरानी में रखते हुए डिजिटल अरेस्ट किया गया तथा मानसिक दबाव बनाकर उससे करीब 1.85 करोड़ रुपये विभिन्न खातों में ट्रांसफर करवा लिए गए।

प्रकरण दर्ज कर साइबर थाना पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान शुरू किया। जांच में अब तक पुलिस पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई और सतर्कता से 40 लाख रुपये रिफंड करवाए गए, जबकि 22 लाख रुपये की अतिरिक्त साइबर ठगी होने से भी बचा लिए गए। जांच के दौरान पुलिस टीम को आरोपी की लोकेशन सवाईमाधोपुर जिले में मिली। इसके बाद टीम ने लगातार पीछा करते हुए करीब 500 किलोमीटर तक निगरानी रखी और अंतत: आरोपी जनकराज पुत्र भागचंद मीणा (25) निवासी पिलौदा, जिला सवाईमाधोपुर को गिरफ्तार कर लिया।

राजस्थान में भी सरकारी कर्मचारियों के लिए 2 दिन के वर्क फ्रॉम होम की तैयारी

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने की अपील के बाद राजस्थान सरकार भी

बड़े बदलावों की तैयारी में नजर आ रही है। राज्य में सरकारी कर्मचारियों को सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम (WFH) की सुविधा देने पर मंथन किया जा रहा है। हालांकि इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन सरकार के स्तर पर विभिन्न विभागों से सुझाव मांगे गए हैं। कहा जा रहा है सरकार जल्द WFH जैसे कुछ बड़े फैसले ले सकती है।

सीएम भजनलाल शर्मा खुद भी ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण को लेकर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने हाल ही में अपने बड़े काफिले की गाड़ियों की संख्या कम करने के साथ इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग शुरू किया है । राजस्थान के मंत्रियों और नेताओं ने भी अपना काफिला छोटा कर दिया है और ईवी का इस्तेमाल कर रहे हैं।

राजस्थान पुलिस की सघन नाकाबंदी से अपराधियों में हड़कंप, 47 हजार वाहनों की जांच, 274 आरोपी गिरफ्तार

हैलो सरकार न्यूज

जयपुर। महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर राजस्थान पुलिस द्वारा प्रदेशभर में चलाए गए दो दिवसीय सघन नाकाबंदी अभियान ने अपराधियों, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों और असामाजिक तत्वों में हड़कंप मचा दिया। अभियान के दौरान कुल 810 नाकाबंदी पॉइंट्स लगाकर 47 हजार से अधिक वाहनों की जांच की गई, जबकि विभिन्न धाराओं में 274 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस कानून एवं व्यवस्था वी के सिंह ने बताया कि शनिवार 16 मई को शाम 7 से रात 10 बजे तक भरतपुर, उदयपुर व कोटा रेंज और रविवार 17 मई सुबह 3 से 6 बजे तक बीकानेर, जोधपुर व जयपुर रेंज के सभी प्रमुख मार्गों पर सघन चेकिंग की गई। इस दौरान पुलिस ने दोपहिया और चौपहिया वाहनों की व्यापक जांच करते हुए ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार प्रदेशभर में कुल 24,573 दोपहिया और 22,531 चौपहिया वाहनों की जांच की गई।

11 हजार से ज्यादा एमवी एक्ट कार्रवाई

अभियान के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन चलाने, फर्जी या बिना नंबर प्लेट और काली फिल्म लगे वाहनों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की गई। पुलिस ने कुल

11,504 मोटर व्हीकल एक्ट की कार्रवाई की। इनमें 757 शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर, 1667 बिना हेलमेट चालकों पर, 1484 बिना सीट बेल्ट, 191 मोबाइल पर बात करते वाहन चालक, 1438 संदिग्ध या बिना नंबर प्लेट वाले वाहन तथा 1017 काली फिल्म लगे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई शामिल रही।

उदयपुर और अजमेर रेंज सबसे आगे

नाकाबंदी अभियान में उदयपुर रेंज सबसे आगे रही, जहां 2647 एमवी एक्ट के मामले दर्ज किए गए। अजमेर रेंज में 2576 कार्रवाई दर्ज हुई। जयपुर रेंज में 1795, कोटा में 1768, भरतपुर रेंज में 1735, जोधपुर रेंज में 968 और बीकानेर रेंज में 15 कार्रवाई कर नियम तोड़ने वालों पर शिकंजा कसा गया।

274 की गिरफ्तारी

अभियान के दूसरे चरण में पुलिस ने अपराधियों, तस्करों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ विशेष कार्रवाई करते हुए कुल 274 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान 12 प्रकरण आर्म्स एक्ट, 41 आबकारी अधिनियम के, 10 एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण तथा 62 अन्य विशेष एवं स्थानीय कानूनों के तहत मामले दर्ज किए गए। जिसमे 73 अपराधियों को विभिन्न एफआईआर और प्रकरणों में गिरफ्तार किया गया, जबकि 170 बीएनएसएस के तहत 201 व्यक्तियों को निरोधात्मक कार्रवाई में पकड़ा गया।

हथियार, शराब और वाहन भी जब्त

अभियान के दौरान कई स्थानों पर अवैध हथियार, शराब और संदिग्ध वाहन भी जब्त किए गए। कोटा रेंज में 5 धारदार हथियार, 120 पव्वे देशी शराब, 2 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई। वहीं 27 वाहनों को जब्त कर कार्रवाई की गई। भरतपुर रेंज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लीटर अवैध शराब बरामद की और एमवी एक्ट की धारा 207 के तहत 61 संदिग्ध वाहनों को सीज किया। एडीजी सिंह ने कहा कि अपराध नियंत्रण, सड़क सुरक्षा और संदिग्ध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए इस प्रकार के संयुक्त अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे।

राजस्थान हाईकोर्ट ने आटा-साटा प्रथा को सौदेबाजी बताया

हैलो सरकार न्यूज, जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने क्रूरता के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री पारित करते हुए कहा कि नाबालिग बच्चों से जुड़ी आटा-साटा प्रथा बच्चों, विशेषकर लड़कियों, को

बेटी किसी दूसरे बेटे की शादी की गारंटी नहीं

वैवाहिक सौदेबाजी का माध्यम बना देती है। न्यायाधीश अरुण मोंगा और न्यायाधीश सुनील बेनीवाल की खंडपीठ ने पत्नी की ओर से दायर अपील स्वीकार करते हुए बीकानेर फैमिली कोर्ट के 24 सितंबर 2025 के आदेश को रद्द कर दिया। फैमिली कोर्ट ने हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत दायर तलाक याचिका खारिज कर दी थी।

मामले में पत्नी ने दहेज की मांग, मारपीट और प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। उसका कहना था कि उससे मोटरसाइकिल और सोने के आभूषणों की मांग की गई तथा उसे ससुराल से निकाल दिया गया। वहीं पति ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि विवाह आटा-साटा प्रथा के तहत हुआ था, जिसके अंतर्गत उसकी बहन का विवाह भी अपीलकर्ता के भाई से किया गया था। पति का कहना था कि उसकी बहन की ओर से बालिग होने के बाद मुकलावा करने से इनकार करने के कारण विवाद शुरू हुआ।

मानव जीवन का लेन-देन

खंडपीठ ने कहा कि जिसे सामुदायिक परंपरा बताया जाता है, वह वास्तव में मानव जीवन का लेन-देन है। एक बालिका किसी पारस्परिक सौदे की कीमत नहीं हो सकती। बेटी किसी दूसरे बेटे के विवाह की गारंटी नहीं है। बचपन से दबाव और सामाजिक शर्तों के बाद बालिग होने पर दी गई सहमति को स्वतंत्र सहमति नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि आटा-साटा जैसी व्यवस्था बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन करती है और ऐसी प्रथाओं को कानून तथा समाज दोनों स्तरों पर अस्वीकार किया जाना चाहिए।

जमानत रद्द करने से इनकार

वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट ने एनडीपीएस मामले में आरोपी महिला पुलिस अधिकारी सीमा जाखड़ की जमानत रद्द करने से इनकार कर

दिया। कोर्ट ने कहा कि जमानत रद्द करना एक कठोर कदम है और केवल आरोपों की गंभीरता के आधार पर पहले से दी गई जमानत को निरस्त नहीं किया जा सकता। न्यायाधीश अशोक कुमार जैन की एकल पीठ ने राज्य सरकार की ओर से दायर जमानत निरस्तीकरण याचिका खारिज करते हुए कहा कि राज्य को ऐसी याचिका दायर करने से पहले उचित कानूनी सलाह लेनी चाहिए थी।

मामला सिरोही जिले के बरलूट थाने में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार 14 नवंबर 2021 को कार में जा रहे रमेश कुमार और दिनेश कुमार के पास से 141 किलो डोडा पोस्त बरामद हुआ था। आरोप है कि उस समय बरलूट थानाधिकारी रही सीमा जाखड़ ने सह आरोपी हेमाराम और अशोक से 10 लाख रुपए की रिश्वत लेकर मामले को कमजोर किया।

बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता धीरेंद्र सिंह और अधिवक्ता प्रियंका बोराणा ने कहा कि प्रतिवादी ने जमानत की किसी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है, इसलिए जमानत रद्द करने का कोई आधार नहीं बनता। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि जमानत रद्द करने और जमानत आदेश को अवैध बताकर निरस्त करने में अंतर होता है। कोर्ट ने कहा कि जमानत तभी रद्द की जा सकती है जब आरोपी जमानत का दुरुपयोग करे, साक्ष्यों से छेड़छाड़ करे, गवाहों को प्रभावित करे या न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डाले।

ट्रंप की चीन यात्राः बड़े बे आबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले

ट्रंप ने अमेरिका वापस लौटने के बाद कहा कि शी जिनपिंग के साथ हुई बैठक को इतिहास में दो महान शक्तियों (G 2) की ऐतिहासिक मुलाक़ात के रूप में याद किया जाएगा।उन्होंने इस मुलाक़ात को अविस्मरणीय भी कहा। उन्होंने बताया कि यह 'दो महान देशों के नेताओं की मुलाक़ात थी । चीन यात्रा के बाद ईरान पर बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन दोनों यह मानते हैं कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिलने चाहिए और हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य को 'तुरंत खोलना' ज़रूरी है।

(लेखक - तनवीर जाफ़री)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गत 13-14 मई को चीन का बहुप्रतीक्षित दौरा किया। विश्व की इन दोनों महाशक्तियों के प्रमुखों की मुलाक़ात पर पूरे विश्व की निगाहें लगी हुई थीं। ख़ासकर अमेरिका-ईरान के मध्य चल रहे तनाव के बीच इस मुलाक़ात को काफ़ी अहम माना जा रहा था। दुनिया की नज़रें इस बात पर भी टिकी थीं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जोकि अनेक फ़्राँस,ब्रिटेन व यूक्रेन जैसे कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ अपनी असामान्य हरकतों से पेश आने व असहज करने वाले बयानों के लिये सुर्ख़ियों में रहते हैं, आख़िर चीन में उनकी भाषा,रवैय्या व बर्ताव कैसा रहेगा। बहरहाल,जिस अमेरिकी राष्ट्रपति के आगमन पर दुनिया के तमाम देश अपनी पलकें बिछाये रहते हैं और प्रायः अमेरिकी राष्ट्रपति के समकक्ष ही हवाई अड्डे पर उनका स्वागत करते हैं वहीं बीजिंग में उनके स्वागत के लिये चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग स्वयं नहीं पहुंचे बल्कि उपराष्ट्रपति हान झेंग ने राष्ट्रपति ट्रंप का स्वागत किया। हान झेंग हालांकि सीधे तौर पर चीन के विदेश मंत्री नहीं हैं परन्तु विदेश मामलों में उनकी भूमिका मुख्यतः कूटनीतिक प्रतिनिधित्व, उच्च-स्तरीय मुलाक़ातें , और द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने की होती है।

ट्रंप और जिनपिंग के बीच बीजिंग में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान घटी एक असामान्य घटना ने पूरे विश्व का ध्यान अपनी तरफ़ खींचा। बैठक के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अपने स्थान से उठने के बाद ट्रंप ने शी जिनपिंग के पास रखी उनकी व्यक्तिगत 'डायरी' के पन्ने पलट कर चुपके से झांकने की कोशिश की। 'निजी ताक-झांक' की इस हरकत को विशेषज्ञों व अंतर्राष्ट्रीय मीडिया द्वारा ट्रंप की व्यक्तिगत शैली से जोड़कर देखा गया। इस घटना को दस्तावेज़ या नोट में बिना पूछे झांकना, दूसरे नेता को 'पलायन' या नियंत्रण की स्थिति में दिखाना और संवाद दौरे के दौरान नर्म दबाव बनाने की चाल चलना आदि के रूप में भी परिभाषित किया गया। दुनिया ने चीन दौरे के दौरान उसी राष्ट्रपति ट्रंप राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बॉडी लैंग्वेज पर भी नज़र रखी।

राष्ट्रपति ट्रंप चीन में अत्यंत संतुलित भाषा का प्रयोग करते और अपने चीनी समकक्ष के सामने पूरी नरमी से पेश आते दिखाई दिये। अपनी चीन यात्रा के बाद अमेरिकी प्रशासन और स्वयं राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा कई स्तरों पर बयान जारी किए गए जिनमें इस यात्रा को 'ऐतिहासिक' और 'सफल' बताया गया। ट्रंप ने अमेरिका वापस लौटने के बाद कहा कि शी जिनपिंग के साथ हुई बैठक को इतिहास में दो महान शक्तियों (G 2) की ऐतिहासिक मुलाक़ात के रूप में याद किया जाएगा।उन्होंने इस मुलाक़ात को अविस्मरणीय भी कहा। उन्होंने बताया कि यह 'दो महान देशों के नेताओं की मुलाक़ात थी । चीन यात्रा के बाद ईरान पर बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन दोनों यह मानते हैं कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिलने चाहिए और हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य को 'तुरंत खोलना' ज़रूरी है। परन्तु यह बात ट्रंप ने अमेरिका जा कर तो कही जबकि चीन की ओर से अपने बयान में इस बात का कोई ज़िक्र नहीं हुआ। ट्रंप ने अपनी इस यात्रा को 'सौदेबाज़ी की सफलता' और अमेरिकी उद्योगों के लिए बड़े अवसर के रूप में भी पेश किया।

उधर चीन की ओर से ट्रंप को ताइवान को लेकर सख़्त शब्दों में चेतावनी दी गयी जिसके बाद ताइवान मुद्दे पर ट्रंप की भाषा और रुख़ दोनों ही बदल गये। ट्रंप की यात्रा के बाद चीन ने अपनी 'रेड लाइन' को दोहराया और ख़ासकर ताइवान मुद्दे पर अपना सख़्त लहजा रखा। चीनी विदेश मंत्रालय और राष्ट्रपति पक्ष के बयानों में ताइवान को अपना 'अविभाज्य हिस्सा' बताया गया और यह चेतावनी दी गई कि अगर अमेरिका ने ताइवान के साथ सैन्य रणनीतिक संबंध बनाए या ताइवान को अधिक हथियार बेचे, तो यह दोनों ताक़तों के बीच 'टकराव और यहां तक कि संघर्ष' को न्यौता दे सकता है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ट्रंप के समक्ष चेतावनी भरे अंदाज़ में स्पष्ट शब्दों में ज़ोर देकर कहा कि ताइवान मुद्दा पूरी तरह चीन का 'आंतरिक मामला' है और किसी बाहरी ताक़त को इसमें हस्तक्षेप करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी, अगर इसे सही तरीक़े से नहीं संभाला गया तो दोनों देश टकराव या यहां तक कि संघर्ष की स्थिति में पहुंच सकते हैं। संभवतः यह पहला अवसर था जबकि किसी राष्ट्राध्यक्ष ने अमेरिकी राष्ट्रपति के समक्ष चेतावनी भरे लहजे में टकराव और संघर्ष की बात कही हो।

चीन की इस चेतावनी के बाद जो अमेरिका व्यवहार में ताइवान को अपना सबसे बड़ा राजनीतिक व सैन्य सहयोगी मानता आया है, उसे चीन से अपनी सुरक्षा के नाम पर हथियार देता है और चीन के विरोध के बावजूद उसकी स्वतंत्र जैसी स्थिति को बनाए रखने के लिए रणनीतिक तौर पर समर्थन देता है। उसी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान को चीन से वापसी के बाद अब औपचारिक रूप से ताइवान को आज़ादी का ऐलान करने के ख़िलाफ़ चेतावनी दे दी है। ट्रंप ने कहा है कि मैं नहीं चाहता कि कोई स्वतंत्रता की ओर बढ़े। ट्रंप ने यह भी कहा कि सोचिए, हमें युद्ध लड़ने के लिए 9,500 मील दूर जाना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि हालात शांत हों। मैं चाहता हूं कि चीन भी शांत रहे। ग़ौरतलब है कि जो अमेरिका क़ानूनी तौर पर ताइवान को आत्मरक्षा के लिए संसाधन मुहैया कराने के लिए बाध्य था उसी अमेरिका को चीनी राष्ट्रपति की

चेतावनी के बाद चीन के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए रखने के कारण अब संतुलन साधना पड़ रहा है।

उधर चीन स्पष्ट रूप से ताइवान को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है। और वो ये भी कहता रहता है कि जरूरत पड़ने पर वह बल प्रयोग से उसे अपने अधीन कर सकता है।

चीन ने ईरान युद्ध को लेकर भी अमेरिकी रुख़ का समर्थन करने के बजाये इसे इस तरह की लड़ाई बताया जो 'मूल रूप से होनी ही नहीं चाहिए थी' गोया अमेरिका-इस्राईल द्वारा ईरान पर थोपा गया युद्ध। चीन ने अमेरिका और ईरान के बीच जल्द समाधान की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया। व्यापारिक स्तर पर भी ट्रंप को उतनी बड़ी सफलता हासिल नहीं हुई जितनी उम्मीद की जा रही थी। क्योंकि उनके साथ एलन मस्क,टिम कुक,जेन्सेन हुआंग,संजय मेहरोत्रा,केली ऑर्टबर्ग जैसे विश्व के 17 प्रमुख अमेरिकी उद्योगपति और कॉर्पोरेट अधिकारी बीजिंग गए थे। कुल मिलाकर ट्रंप को बीजिंग से जहां ताइवान को लेकर चेतावनी मिली वहीं ईरान मामले को लेकर भी अपेक्षित सहयोग नहीं मिल सका। ट्रंप की इस यात्रा के लिये बस यही कहा जा सकता है कि बड़े बे आबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले।

(यह लेखक के व्य क्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अ निवार्य नहीं है)

संपादकीय

बात-बेबात और विवाद

इसमें दो राय नहीं कि देश के प्रतिष्ठित व शीर्ष पदों पर विराजमान व्यक्तियों को अपने संस्थानों व सार्वजनिक मंचों पर अपनी बात रखने में अतिरेक में सावधानी बरतनी चाहिए। उससे निकलने वाले शब्दों के अर्थों के कई मायने निकाले जा सकते हैं। ऐसी ही चर्चा देश की शीर्ष अदालत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के हालिया बयानों को लेकर हुई। बताया जाता है कि एक अधिवक्ता द्वारा सीनियर का दर्जा दिए जाने के बाबत दायर याचिका पर खिन्न मुख्य न्यायाधीश ने प्रासंगिक संदर्भ में जो कहा, उसको लेकर सवाल उठे। बताया जा रहा है कि 'उन्होंने मौखिक तौर पर कहा कि समाज में पहले से ऐसे परजीवी हैं जो व्यवस्था पर हमला करते हैं, और आप उनके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं... कुछ युवा ऐसे हैं, जो रोजगार नहीं मिलने और पेशे में जगह न बना पाने के कारण 'कॉकरोच' की तरह हर जगह फैल जाते हैं। उसमें से कुछ सोशल मीडिया पर सक्रिय हो जाते हैं, कुछ आरटीआई कार्यकर्ता बन जाते हैं और फिर हर किसी पर हमला शुरू कर देते हैं।' निश्चय ही हाल के वर्षों में संपादक विहीन सोशल मीडिया में लोगों के अराजक व्यवहार को देखते हुए यह भले ही यह सत्य न हो, कुछ लोग इसे अर्धसत्य बताते हैं। लेकिन न्याय व्यवस्था के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति से इस विषय पर संवेदनशील ढंग से अभिव्यक्ति की अपेक्षा की जाती है। हालांकि, बाद में जस्टिस सूर्यकांत ने 'कॉकरोच' वाले बयान पर कहा है कि 'मीडिया ने उनके शब्दों को गलत ढंग से पेश किया।' उन्होंने अपनी मौखिक टिप्पणी के बाबत कहा कि उनकी बातों को इस तरह पेश किया गया जैसे उन्होंने देश के युवाओं की आलोचना की हो। उनका कथन था कि उनकी टिप्पणी केवल उन लोगों के खिलाफ थीं, जिन्होंने फर्जी या नकली डिग्रियों के सहारे वकालत जैसे पेशों में प्रवेश किया है। ऐसे ही लोग मीडिया, सोशल मीडिया और अन्य सम्मानित पेशों में घुस आए हैं, इसलिए परजीवियों की तरह हैं। उनका इशारा न्यायापालिका पर होने वाले अनुचित हमलों की तरफ था। दरअसल, मुख्य न्यायाधीश ने वकीलों की कानून की डिग्रियों की जांच प्रक्रिया का जिक्र करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ वकीलों द्वारा डाली जाने वाली सामग्री को देखकर उन्हें कई वकीलों की कानूनी डिग्रियों की प्रमाणिकता पर संदेह है। लेकिन इसके साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों, सोशल मीडिया से जुड़े लोगों व सोशल एक्टिविस्ट ने सीजेआई की टिप्पणी को लेकर प्रतिक्रिया दी हैं। राज्यसभा में एक राजद सांसद ने सार्वजनिक चिट्ठी लिखकर मुख्य न्यायाधीश की भाषा को लेकर चिंता जतायी। उनका कहना था कि बेरोजगारों, आरटीआई कार्यकर्ताओं, मीडिया कर्मियों और असहमति व्यक्त करने वालों की तुलना 'कॉकरोच' व 'परजीवी' से करना लोकतंत्र की मूल आत्मा और उसकी बुनियादी संवैधानिक संस्कृति को आहत करने वाला लगता है। आलोचकों का कहना है कि न्यायपालिका से आशा की जाती है कि वह संवैधानिक संयम व गरिमा की अंतिम शरणस्थली बनी रहे। एक आरटीआई कार्यकर्ता का मानना है कि प्रश्न पूछने का अधिकार लोकतंत्र की आत्मा है, ये व्यवस्था पर हमला नहीं, बल्कि उसे मजबूत बनाये रखने में भूमिका है।

मायावती की निष्क्रियता : क्या खत्म हो जाएगी बसपा?

मायावती के इस तरह शांत बैठने और बसपा के कमजोर होने का सीधा फायदा दूसरी पार्टियों को मिल रहा है। बसपा का जो कोर मुस्लिम और दलित वोट बैंक था, उसका एक बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की तरफ चला गया है। वहीं, गरीब और गैर-जाटव दलितों का एक बड़ा वर्ग सरकारी योजनाओं जैसे मुफ्त राशन और आवास के कारण भाजपा के साथ जुड़ गया है।

(लेखक- दिलीप कुमार पाठक)

उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक समय ऐसा था जब मायावती का नाम सुनते ही विरोधी दल अपनी रणनीति बदलने लगते थे। लेकिन आज जमीनी हकीकत पूरी तरह बदल चुकी है। देश की सियासत में यह चर्चा बहुत तेज है कि मायावती की जमीनी स्तर पर बढ़ती निष्क्रियता और पार्टी का लगातार गिरता वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा को खत्म होने की कगार पर ले आया है। नौबत यहां तक आ गई है कि बसपा से उसका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी कभी भी छिन सकता है। अगर हम आंकड़ों को देखें, तो बसपा की हालत इस समय सबसे खराब दौर में है। देश और उत्तर प्रदेश के चारो सदनों को मिलाकर देखें तो पार्टी के पास अब नाममात्र के नेता बचे हैं। लोकसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने वाली बसपा का खाता तक नहीं खुला और देश के सबसे बड़े सदन में उसकी सीटें आज शून्य हैं। देश के उच्च सदन यानी राज्यसभा में बसपा का सिर्फ एक सांसद बचा है, जिनका कार्यकाल नवंबर 2026 में खत्म हो जाएगा। इसके बाद बसपा का कोई नया सांसद राज्यसभा नहीं जा पाएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा में पार्टी के पास विधायक ही नहीं हैं।

जिस उत्तर प्रदेश में कभी मायावती ने चार बार मुख्यमंत्री बनकर सरकार चलाई थी, आज वहां की 403 विधानसभा सीटों में से बसपा के पास केवल एक विधायक बचा है। वहीं, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में भी बसपा की सीटें अब जीरो हो चुकी हैं। इस भारी गिरावट का सबसे बड़ा कारण मायावती की राजनीति करने का तरीका है। पिछले कुछ सालों से वे केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस या सोशल मीडिया पर बयान जारी करने तक सीमित हो गई हैं। वे न तो जनता के मुद्दों पर सड़कों पर उतर रही हैं और न ही महंगाई, बेरोजगारी या दलित उत्पीड़न जैसे मामलों पर कोई बड़ा आंदोलन कर रही हैं। नेता की इस निष्क्रियता के कारण पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता निराश होकर घर बैठ गए या दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए। इसी का नतीजा है कि आम चुनाव में बसपा का कुल वोट शेयर घटकर मात्र दो प्रतिशत के आसपास रह गया। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, इतने कम वोट शेयर और बिना किसी सीट के बसपा का राष्ट्रीय पार्टी का तमगा जाना लगभग तय है। मायावती के इस तरह शांत बैठने और बसपा के कमजोर होने का सीधा फायदा दूसरी पार्टियों को मिल रहा है। बसपा का जो कोर मुस्लिम और दलित वोट बैंक था, उसका एक बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की तरफ चला गया है। वहीं, गरीब और गैर-जाटव दलितों का एक बड़ा वर्ग सरकारी योजनाओं जैसे मुफ्त राशन और आवास के कारण भाजपा के साथ जुड़ गया है। इसके अलावा, युवाओं के बीच चंद्रशेखर आजाद एक नए और आक्रामक दलित नेता के रूप में उभरे हैं, जिन्होंने नगीना सीट से लोकसभा चुनाव जीतकर यह साबित कर दिया कि बसपा का वोटर अब नया विकल्प ढूंढ चुका है।

जमीनी हकीकत यह भी है कि मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को राजनीति में आगे तो बढ़ाया और उन्हें अपना उत्तराधिकारी भी घोषित किया, लेकिन उनके

आक्रामक भाषणों के बाद उन्हें कुछ समय के लिए किनारे कर दिया गया। नेतृत्व के इस असमंजस ने कार्यकर्ताओं को और ज्यादा भ्रमित कर दिया। जब तक पार्टी में युवाओं को खुलकर फैसले लेने की आजादी नहीं मिलेगी, तब तक नए दौर के वोटरों को जोड़ना नामुमकिन है। साफ शब्दों में कहें तो बसपा इस समय अपने अस्तित्व की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रही है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं। अगर मायावती ने अब भी अपनी बंद कमरों वाली रणनीति नहीं बदली, आकाश आनंद जैसे युवा नेताओं को कमान सौंपकर सड़कों पर संघर्ष शुरू नहीं किया, तो बसपा का राजनीतिक वजूद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। क्योंकि राजनीति में शून्य के लिए कोई जगह नहीं होती। अगर बसपा अपनी जमीन छोड़ रही है, तो लोकतंत्र का नियम है कि कोई न कोई उस खाली जगह को भरेगा ही। अब फैसला मायावती को करना है कि वे इतिहास का हिस्सा बनना चाहती हैं या भविष्य का।

(लेखक पत्रकार हैं)

चिंतन सही हो

एक व्यक्ति ने अपने मित्र से साठ रूपए उधार लिए। कुछ दिनों बाद वह आया और बीस रूपए देकर बोला, सारे रूपए आ गए? मित्र ने कहा, साठ दिए थे और तुम बीस लौटा रहे हो, तो अभी चालीस रूपए बाकी रहेंगे। तीस और तीस साठ होते हैं।

उसने कहा, नहीं, दस और दस साठ होते हैं। मैंने साठ रूपए लौटा दिए हैं। मित्र ने कहा, भोले आदमी! दस और दस बीस ही होते हैं। तीस और तीस साठ होते हैं। उसने कहा, मैं इस बात को नहीं मानता। मैं तो यही मानता हूं कि दस और दस साठ होते हैं। मेरी मान्यता मेरे पास और तुम्हारी मान्यता तुम्हारे पास।

ऐसे मानने वाले को विधाता भी नहीं समझा सकता। गणित का नियम -दस और दस बीस होते हैं। कोई व्यक्ति इस गणित के नियम को जानने की बात छोड़कर मानने की बात को ही पकड़ बैठता है तो उसका कोई इलाज नहीं है। हम मानने की बात को छोड़ दें और जानें। सदा जानने का प्रयत्न करें। सदा जानें। हम विशिष्ट उपलब्धियों के लिए प्रयत्न करें। वे प्राप्त हों तो ठीक है, न हों तो कोई बात नहीं। पुरूषार्थ को सही दिशा में लगाएं। पुरूषार्थ निरंतर हमारा साथ दे। हम प्रयत्न को बंद न करें।

पुरूषार्थ को साथ लेकर चलें। मन और शरीर को विशेष आदेश दें। मन जो भटकता रहता है, अनेक प्रवृत्तियों में संलग्न रहता है, बहुत अधिक सक्रिय और गतिशील है, उस पर हम कुछ नियंत्रण करें। मन की सक्रियता को कम करें।

विचार मंथन

पेपर लीक का बम प्रधान पर फोड़ने की तैयारी में राहुल गांधी

(लेखक- सनत जैन)

लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हाथ में नीट-यूजी पेपर लीक का बम आ गया है। यह ऐसा बम है, जिसमें लाखों युवा और उनके करोड़ों परिवारजन का भविष्य और नाराजी जुड़ी हैं। करोड़ों लोगों को प्रभावित करने वाले इस बम को लेकर, राहुल गांधी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने लगातार परीक्षा पेपर लीक होने के मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेने या बर्खास्त करने की सीधी मांग कर दी है। देश के विभिन्न राज्यों में पेपर लीक की 80 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। नीट परीक्षा के 2024 में पेपर लीक हुए थे। इस परीक्षा में बड़ी संख्या में लोग 700 से ज्यादा अंक लेकर हजारों परीक्षार्थी पास हुए थे। जिनके एडमिशन एम्स और अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेज में नीट परीक्षा परिणाम के बाद हुए थे। उस परीक्षा में भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के आरोप लगे थे। उस समय यह मामला रफा-दफा हो गया था। सुप्रीम कोर्ट के बीच में आ जाने के कारण ना तो दोबारा परीक्षा हुई, ना ही परीक्षा परिणाम को लेकर सरकार ने कोई जांच कराई। नीट परीक्षा में लगातार गड़बड़ी की शिकायत आती रही है।

देश में हजारों करोड़ों रुपए का यह ऐसा घोटाला है। जो एम्स और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के नाम पर पिछले कई वर्षों से चल रहा है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों की फीस, निजी कॉलेजों की तुलना में बहुत कम होती है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फीस लाखों रुपए प्रतिवर्ष तक पहुंचती है। ऐसी स्थिति में नीट परीक्षा के माध्यम से सरकारी मेडिकल कॉलेजों में दाखिला दिलाने के नाम पर कोचिंग सेंटर, दलाल इस गोरखधंधे में शामिल होकर करोड़ों रुपए की कमाई कर रहे हैं। परीक्षा से जुड़े लोगों को हर साल करोड़ों रुपयों की कमाई हो रही है। इस बार भी करीब 22 लाख छात्र-छात्राओं ने नीट के फॉर्म भरे थे।

हजारों करोड़ों रुपए की फीस परीक्षार्थियों से वसूली गई। कोचिंग सेंटर में हजारों करोड़ों रुपए छात्र-छात्राओं ने खर्च किए हैं। कई छात्र-छात्राओं ने दो से तीन साल तक रात दिन मेहनत करके इस परीक्षा की तैयारी की थी। पेपर लीक हो जाने से सबके भविष्य में प्रश्न चिन्ह लग गया है। इस मामले को लेकर लगभग सभी राज्यों के युवा अब सड़कों पर आ गए हैं। दक्षिण के राज्यों ने अलग तरह से प्रवेश परीक्षा संचालित करने की बात करना शुरू कर दी है। अभी तक 80 बार से ज्यादा विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। युवा वर्ग इस समय काफी नाराज है। सभी राज्यों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी ही एक ऐसे नेता हैं, जिन्होंने खुलकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने या बर्खास्त करने का दबाव प्रधानमंत्री पर बनाना शुरु कर दिया है।

इस्तीफे के इस बम को आसानी से डिफ्यूज कर पाना केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के बस की बात नहीं होगी। इस बार इस लड़ाई में राहुल गांधी के साथ बड़े पैमाने पर युवा भी साथ में है। रही सही कसर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा बेरोजगारों और फर्जी डिग्री धारकों के लिए परजीवी होने तथा जो असंवेदनशील टिप्पड़ी की है, उसके बाद से युवाओं में नाराजी बढ़ गई है। न्यायपालिका पर विश्वास भी एक तरह से कम हो गया है।

जांच एजेंसी सीबीआई हमेशा छात्रों पर कार्यवाही करती है। व्यापम से लेकर अभी तक दर्जनों बार व्यापम और नीट के जो पेपर लीक हुए हैं, उसमें कार्यवाही हमेशा निर्दोष छात्रों के ऊपर हुई है। कभी किसी भी धंधेबाज और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही नहीं की गई है। नैतिकता या जिम्मेदारी के आधार पर कुर्सी पर बैठे हुए नेताओं ने कभी इस्तीफा नहीं दिया है। जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कभी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जिसके कारण युवा नाराज होकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है। इस समय मंहगाई, बेरोजगारी तथा पेपर लीक को लेकर राहुल गांधी के हाथ में एक ऐसा मौका लग गया है, जिससे वह सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं।

12 साल में पहली बार मोदी सरकार के किसी मंत्री से, विपक्ष ने इस्तीफा के लिए दबाव बनाया है। यह दबाव खाली जाएगा, ऐसा दिखता नहीं है। राहुल गांधी अब विपक्ष की राजनीति करना सीख गए हैं। मौके का फायदा किस तरह से उठाया जाता है, यह जान गए हैं। वर्तमान स्थिति में छात्रों और युवाओं के गुस्से को देखते हुए धर्मेंद्र प्रधान को ढाल बनाकर इस्तीफा देने का दबाव बना चुकें हैं। आर्थिक संकट से घिरी सरकार पर राहुल गांधी लगातार हमले कर रहे हैं। इसकी परिणति किस रुप में होगी कहना मुश्किल है।

परमाणु संयंत्र पर हमले से तेल बाजार में भूचाल, अंतरराष्ट्रीय तनाव चरम पर

भू-राजनीतिक तनाव से कच्चे तेल में भारी तेजी, ब्रेंट क्रूड 110 डॉलर के पार

नई दिल्ली।

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर हुए ड्रोन हमले के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें दो सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिका-ईरान शांति वार्ता के ठप पड़ने से निवेशक घबराए हुए हैं। हमले की खबर आते ही कच्चे तेल के दोनों बेंचमार्क में जोरदार उछाल आया। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 1.32 फीसदी बढ़कर 110.70 डॉलर प्रति बैरल पर, जबकि अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड 1.75 फीसदी की तेजी के साथ 107.26 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। यह 5 मई के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। अमीराती अधिकारियों ने बराकाह परमाणु संयंत्र पर हमले की पुष्टि करते हुए इसे आतंकी हमला करार दिया और करारा जवाब देने की बात कही। इसी बीच सऊदी अरब ने भी इराकी हवाई क्षेत्र से आए तीन लड़ाकू ड्रोनों को मार गिराने का दावा किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य विकल्पों पर चर्चा ने तनाव को और बढ़ा दिया है। आईजी मार्केट के विश्लेषकों के अनुसार ये ड्रोन हमले वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए एक गंभीर चेतावनी हैं। यदि अमेरिका या इज़राइल की ओर से ईरान पर कोई जवाबी कार्रवाई होती है, तो खाड़ी क्षेत्र के महत्वपूर्ण ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमले और तेज हो सकते हैं। शांति समझौते की उम्मीदें खत्म होने से तेल की कीमतों में यह तेजी जारी रहने की आशंका है।

मिड-स्मॉलकैप फंडों में मजबूत वापसी, पर विशेषज्ञ दे रहे फूंक-फूंक कर कदम चलने की सलाह

अप्रैल में मिडकैप ने 11 फीसदी और स्मॉलकैप ने 13.5 फीसदी की वृद्धि दर्ज की

नई दिल्ली ।

अप्रैल महीने में मिडकैप और स्मॉलकैप फंडों ने शानदार प्रदर्शन किया, जहां मिडकैप ने औसतन 11 फीसदी और स्मॉलकैप ने 13.5 फीसदी का इजाफा दर्ज किया। यह वृद्धि निवेशकों के लिए राहत लेकर आई है, लेकिन बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इस श्रेणी में अभी भी कुछ चिंताएं बरकरार हैं। इसलिए, निवेशकों को इस चमकती वापसी के बावजूद अपने कदमों को सावधानी से आगे बढ़ाना चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार यह मौजूदा उछाल 2024 के आखिरी महीनों के दौरान इन श्रेणियों में आई भारी गिरावट के बाद की तेजी है, जब मिडकैप और स्मॉलकैप में कुछ जगह 25 से 35 फीसदी की गिरावट देखी गई थी। निप्पॉन इंडिया म्युचुअल फंड के एक अे धिकारी बताते हैं`` कि इस गिरावट की वजह अत्यधिक महंगे शेयर और राजकोषीय व मौद्रिक नीतियों में सख्ती के बाद वृद्धि के कमजोर आसार थे। इस गिरावट ने शेयरों को कम कीमत पर लुभावना बना दिया, जिससे निवेशकों को दोबारा निवेश करने का अवसर मिला। एडलवाइस म्युचुअल फंड के एक अे धिकारी के अनुसार मार्च में बाजार का 10 फीसदी से ज्यादा लुढ़कना अनुमान से कहीं अधिक था। मौजूदा तेजी भू-राजनीतिक समस्याओं के जल्द सुलझने और कमाई में इजाफे की रफ्तार कम न होने की उम्मीदों पर आधारित है। साथ ही, घरेलू खपत में भी पूरी तरह गिरावट नहीं आई है। जीएसटी संग्रह, ऋण उठान में वृद्धि और कुछ क्षेत्रों में कंपनियों का मुनाफा बताता है कि देश के भीतर खपत बरकरार है। मंदी के बावजूद खुदरा निवेशकों ने एसआईपी के माध्यम से शेयरों में निवेश जारी रखा है। आगे की तेजी भू-राजनीतिक तनाव में कमी और कच्चे तेल की कीमतों पर निर्भर करेगी। प्लान अहेड वेल्थ एडवाइजर्स के विशाल धवन के मुताबिक, तेल की कीमत लगभग 85 डॉलर प्रति बैरल और रुपये में ठहराव महंगाई को थामने और आय तथा विदेशी निवेश को बल देगा। शेयरों की कीमत के हिसाब से अर्निंग में इजाफा भी महत्वपूर्ण है।

शेयर बाजार में बढ़ा म्यूचुअल फंड्स का दबदबा, कमजोर पड़ी एलआईसी की पकड़

पांच साल में तेजी से घटा एलआईसी का हिस्सा

नई दिल्ली ।

भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की शेयर बाजार पर पकड़ लगातार कमजोर हो रही है। दूसरी ओर म्यूचुअल फंड उद्योग का दबदबा तेजी से बढ़ा है, जो पिछले 14 वर्षों में प्रमुख बदलाव का संकेत है। हाल ही में जारी` किए गए आंकड़ों के अनुसार यह अंतर लगातार पांचवें साल बढ़ा है। मार्च 2012 में, एलआईसी के पास सार्वजनिक कारोबार के लिए उपलब्ध सूचीबद्ध शेयरों के मूल्य का 10.67 फीसदी हिस्सा था, जो मार्च 2026 तक घटकर 7.42 फीसदी रह गया। इसी अवधि में, म्यूचुअल फंड उद्योग का हिस्सा 7.06 फीसदी से बढ़कर 22.92 फीसदी हो गया है। एक अे धिकारी ने बताया कि म्यूचुअल फंडों का बढ़ता दबदबा खुदरा निवेशकों के निरंतर निवेश का परिणाम है। यह रुझान फिलहाल धीमा होता नहीं दिख रहा। उन्होंने कहा कि बाजार हिस्सेदारी घटने के बावजूद, एलआईसी अभी भी सबसे बड़ी अकेली परिसंपत्ति प्रबंधक बनी हुई है, जिसकी इक्विटी परिसंपत्तियां

सबसे बड़े म्यूचुअल फंड से कम से कम दोगुनी हैं। उनके अनुसार म्यूचुअल फंडों के विपरीत, एलआईसी पर मोचन (रिडम्पशन) का वैसा दबाव या मासिक खुलासे की बाध्यता नहीं होती। एलआईसी की कुल इक्विटी होल्डिंग्स का मूल्य 15.11 लाख करोड़ रुपये है। रिलायंस इंडस्ट्रीज (1.2 लाख करोड़ रुपये) में उसकी सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। इसके अतिरिक्त, एसबीआई, एलएंडटी, आईटीसी और इन्फोसिस में भी उसकी 50,000 करोड़ रुपये से अधिक की हिस्सेदारी है।

पश्चिम बंगाल में बड़े टेक निवेश की तैयारी, केंद्र कर रहा वैश्विक दिग्गजों से बात

कोलकाता । केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल को एक प्रमुख तकनीकी केंद्र बनाने की दिशा में सक्रिय हो गई है। राज्य में डेटा सेंटर, हाइपरस्केलर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट (आरएंडडी) हब में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गूगल, अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट जैसी वैश्विक कंपनियों के साथ-साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज और अदाणी समूह जैसे भारतीय समूहों से बातचीत की जा रही है। सेमीकंडक्टर कंपनियों और अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) को भी राज्य में लाने का प्रयास जारी है। यह पहल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राज्य चुनावों में जीत के बाद तेज हुई है, जिसने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के 15 साल पुराने शासन का अंत किया। पश्चिम बंगाल में औद्योगिक और आर्थिक विकास को फिर से गति देना भाजपा के चुनावी अभियान का प्रमुख मुद्दा था। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की है कि बातचीत सकारात्मक रही है। फिलहाल, राज्य सॉफ्टवेयर निर्यात में केवल 2.1 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ सातवें स्थान पर है, जो इसे कर्नाटक जैसे अग्रणी राज्यों से काफी पीछे रखता है। जून तक कुछ निवेशों को अंतिम रूप देकर घोषित किए जाने की उम्मीद है।

प्रूडेंशियल भारती लाइफ में 75 फीसदी हिस्सेदारी खरीदेगा

चेसिस निर्यात में भारत की बड़ी छलांग

मुंबई ।

ब्रिटिश बीमा दिग्गज प्रूडेंशियल ने भारती लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में 75 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने पर सहमति जताई है, जो भारत में उसके परिचालन को बेहतर बनाने की नई रणनीति का हिस्सा है। रॉयटर्स के अनुसार, इस सौदे में 35 अरब रुपए का प्रारंभिक नकद भुगतान शामिल है, साथ ही शर्तों के आधार पर 7 अरब डॉलर अतिरिक्त देय हो सकते हैं। इस अधिग्रहण के बाद भारती लाइफ इंश्योरेंस का बहुमत स्वामित्व प्रूडेंशियल के पास होगा। हालांकि, नियामक मंजूरी के लिए कंपनी को आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ में अपनी हिस्सेदारी 10 फीसदी से कम करनी होगी। यह कदम भारत के जीवन बीमा कारोबार में बहुमत स्वामित्व हासिल करने की प्रूडेंशियल की रणनीति का हिस्सा है। भारती लाइफ, भारती एयरटेल और 360 वन के साथ रणनीतिक वितरण समझौतों पर भी विचार करेगी। इसी बीच, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के इंजन लगे चेसिस का निर्यात 302.3 मिलियन डॉलर (28.98 अरब डॉलर) तक पहुंच गया, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात (144.3 मिलियन) सबसे बड़ा आयातक रहा। यह वृद्धि वैश्विक मांग और देश की बढ़ती ऑटोमोबाइल विनिर्माण क्षमता को दर्शाती है। फिलीपीन, बांग्लादेश और अमेरिका भी प्रमुख आयातक रहे।

रुपए में ऐतिहासिक गिरावट डॉलर के आगे बेबस, क्या 100 की ओर जा सकता है?

कच्चे तेल की कीमतें, वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और विदेशी बिकवाली ने बढ़ाई मुश्किलें

नई दिल्ली ।

भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगातार दबाव में है और हाल ही में रिकॉर्ड निचले स्तर 96.14 प्रति डॉलर तक पहुंच गया है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, विदेशी निवेशकों की बिकवाली और भू-राजनीतिक तनाव जैसे कई कारकों ने रुपये पर चौतरफा दबाव बढ़ाया है, जिससे इसकी स्थिति और नाजुक हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मौजूदा हालात नहीं सुधरे तो रुपया डॉलर के मुकाबले 100 के मनोवैज्ञानिक स्तर के करीब जा सकता है। रुपये की इस कमजोरी के पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं। अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में बढ़ोतरी और अमेरिका में ऊंची ब्याज दरों के चलते विदेशी निवेशक भारत जैसे उभरते बाजारों से पूंजी निकालकर अमेरिकी बाजारों की ओर बढ़ रहे हैं। जब ये निवेशक रुपये बेचकर डॉलर खरीदते हैं, तो डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया कमजोर होता है। इसके अलावा, दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता या युद्ध जैसे हालात होने पर निवेशक सुरक्षित निवेश के तौर पर अमेरिकी डॉलर की ओर रुख करते हैं, जिससे उसकी मांग और बढ़ जाती है। भारत अपनी 90 फीसदी से अधिक तेल जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है। कच्चे तेल की मौजूदा ऊंची कीमतें (लगभग 111 डॉलर प्रति बैरल) देश के आयात बिल को बढ़ा रही हैं, जो रुपये पर और दबाव डालता है। मिडिल ईस्ट में बढ़ता भू-राजनीतिक तनाव भी निवेशकों की चिंता बढ़ा रहा है, जिससे डॉलर को सुरक्षित आश्रय के रूप में देखा जा रहा है। कमजोर रुपये का सबसे बड़ा असर आयात पर

निर्भर सेक्टरों जैसे एविएशन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और एफएमसीजी पर पड़ेगा, क्योंकि उनकी लागत बढ़ जाएगी। इससे स्मार्टफोन, लैपटॉप, लग्जरी कार और कई दवाइयां महंगी हो सकती हैं, जिससे आम लोगों पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा। हालांकि, कुछ सेक्टरों को फायदा भी मिल सकता है। आईटी सर्विसेज, फार्मा, टेक्सटाइल और स्पेशलिटी केमिकल्स जैसी निर्यात आधारित कंपनियों की कमाई बढ़ सकती है, क्योंकि उन्हें डॉलर में भुगतान मिलता है और रुपये में बदलने पर उन्हें अधिक राशि मिलती है। इससे भारतीय उत्पादों का निर्यात भी विदेशों में सस्ता हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार अगर कच्चा तेल 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचता है और भू-राजनीतिक तनाव बढ़ता है, तो रुपया 100 के स्तर के करीब जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) रुपये को स्थिर रखने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग और मौद्रिक नीति में बदलाव जैसे कदम उठा सकता है।

अदाणी ग्रुप बिहार के इन्फ्रास्ट्रक्चर पर करेगा 60,000 करोड़ तक निवेश अदाणी

चेयरमैन गौतम अदाणी ने सारण में अखण्ड ज्योति आई हॉस्पिटल के उद्घाटन पर की घोषणा

पटना ।

अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने बिहार के इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए अगले तीन से चार वर्षों में 50,000 करोड़ से 60,000 करोड़ रुपये तक के विशाल निवेश का ऐलान किया है। उन्होंने यह महत्वपूर्ण घोषणा सारण के मस्तीचक में अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल- अदाणी सेंटर फॉर आई डिजीज के उद्घाटन समारोह के दौरान की।

गौतम अदाणी ने कहा कि अदाणी ग्रुप का लक्ष्य बिहार की प्रगति और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम करना है। उन्होंने बताया कि भागलपुर जिले के पीरपैंती में 2,400 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास हो चुका है और उस पर काम चल रहा है। इसके साथ ही, राज्य में कई रोड प्रोजेक्ट्स पर भी अदाणी ग्रुप सक्रिय है। अदाणी ने बिहार के विकास की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा` कि बिहार की ग्रोथ का समय आ गया है। यहां इन्फ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिकीकरण की काफी जरूरत है, जिसका लाभ राज्य की जनता को उठाना

चाहिए। उनकी पत्नी और अदाणी फाउंडेशन की चेयरपर्सन प्रीति अदाणी के साथ बिहार पहुंचे गौतम अदाणी ने इस पावन भूमि, विशेषकर मस्तीचक में आकर खुशी और गौरव व्यक्त किया। उन्होंने गायत्री शक्तिपीठ के दर्शन से असीम शांति मिलने और समाज के लिए कुछ बेहतर करने की प्रेरणा मिलने की बात कही।

गोल्डलाइन फार्मा आईपीओ ने रचा इतिहास, निवेशकों को बंपर मुनाफे की उम्मीद

840 गुना से अधिक सब्सक्राइब हुआ आईपीओ, 19 मई को लिस्टिंग

मुंबई ।

गोल्डलाइन फार्मास्युटिकल के आईपीओ ने निवेशकों के बीच अभूतपूर्व उत्साह जगाया है। इसकी जबरदस्त प्रतिक्रिया और ग्रे मार्केट में 46 फीसदी से अधिक प्रीमियम पर कारोबार इसकी मजबूत लिस्टिंग की प्रबल संभावना दर्शाते हैं। गोल्डलाइन फार्मास्युटिकल का आईपीओ 12 मई को खुला था और 14 मई तक निवेश के लिए उपलब्ध रहा।

इस दौरान कंपनी के 43 रुपए प्रति शेयर के इश्यू प्राइस वाले आईपीओ को कुल 840.74 गुना सब्सक्रिप्शन मिला, जो एक रिकॉर्ड है। लगभग 12 करोड़ रुपए के इस आईपीओ के शेयरों की लिस्टिंग मंगलवार, 19 मई को होनी है। ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम 20 रुपए तक पहुंच गया है, जिससे यह करीब 63 रुपए पर लिस्ट हो सकता है। यह आईपीओ पाने वाले निवेशकों को लिस्टिंग के दिन ही 46 फीसदी से ज्यादा के बंपर मुनाफे का संकेत देता है। गोल्डलाइन फार्मास्युटिकल गोल्डलाइन ब्रांड से फार्मा उत्पादों की मार्केटिंग करती है। कंपनी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स से उत्पाद तैयार करवाकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सहित 7 राज्यों में वितरित करती है।

मारुति सुजुकी ने खरखौदा में दूसरा संयंत्र शुरू किया, उत्पादन क्षमता दोगुनी हुई

कंपनी की कुल क्षमता बढ़कर 26.5 लाख इकाई पर पहुंची

नई दिल्ली ।

देश की सबसे बड़ी कार निर्माता, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (एमएसआईएल) ने सोमवार को हरियाणा के खरखौदा स्थित अपनी विनिर्माण इकाई के दूसरे संयंत्र में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की घोषणा की है। इस कदम से कंपनी की उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो बाजार में बढ़ती मांग को पूरा करने में सहायक होगी। मारुति सुजुकी के इस नए संयंत्र के शुरू होने से खरखौदा इकाई की वार्षिक उत्पादन क्षमता में 2.5 लाख इकाई का इजाफा हुआ है। इसके साथ ही खरखौदा संयंत्र की कुल क्षमता अब 5 लाख इकाई प्रति वर्ष हो गई है। इस विस्तार के परिणामस्वरूप कंपनी के गुरुग्राम, मानेसर, खरखौदा (हरियाणा) और हंसलपुर (गुजरात) स्थित सभी संयंत्रों की कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता बढ़कर 26.5 लाख इकाइयों पर पहुंच गई है। कंपनी ने बताया कि पूरी तरह से संचालित होने पर खरखौदा संयंत्र मूल कंपनी सुजुकी के सबसे बड़े चार पहिया वाहन विनिर्माण स्थलों में से एक होगा, जिसकी क्षमता प्रति वर्ष 10 लाख वाहन बनाने

की होगी। मारुति सुजुकी ने पहले ही वित्त वर्ष 2026-27 तक पांच लाख इकाइयों की अतिरिक्त क्षमता जोड़ने की योजना की घोषणा की थी। वर्तमान में इस इकाई में कॉम्पैक्ट एसयूवी ब्रेजा और मिड-एसयूवी मॉडलों का उत्पादन किया जा रहा है। यह विस्तार भविष्य की विकास योजनाओं के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

पटसन संकट गहराया मिलें बंद, हजारों श्रमिक बेरोजगार, सरकार से हस्तक्षेप की अपील

हुगली में 14 मिलें बंदी की कगार पर, 75,000 श्रमिक प्रभावित

कोलकाता ।

पश्चिम बंगाल का पटसन उद्योग कच्चे पटसन की भारी कमी और कीमतों में बेतहाशा उछाल के कारण गहरे संकट में है। इस स्थिति ने बड़े पैमाने पर मिल बंद होने और हजारों श्रमिकों के बेरोजगार होने की आशंका पैदा कर दी है, जिसके चलते उद्योग ने राज्य में नवगठित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन (आईजेएमए) के अनुसार हुगली औद्योगिक क्षेत्र में कम से कम 14 मिलें या तो बंद हो गई हैं या कच्चे पटसन की कमी और अव्यवहार्य लागत के कारण गंभीर उत्पादन बाधा का सामना कर रही हैं। इससे उत्तर 24 परगना और हुगली जिलों सहित आसपास के क्षेत्रों में अनुमानित 75,000 श्रमिक पहले ही अनैच्छिक बेरोजगारी का शिकार हो चुके हैं। जूट बेलर्स एसोसिएशन (जेबीए) की 17,100 रुपये प्रति क्विंटल की उच्च दरों और व्यापार पर प्रतिबंध ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है। उद्योग प्रतिनिधियों का आरोप है कि यह संकट केवल मौसमी कमी नहीं, बल्कि लंबे समय से जारी सट्टा भंडारण, विकृत बाजार परिस्थितियों एवं प्रशासनिक निष्क्रियता का परिणाम है। शून्य-भंडार आदेश को भी एक दोधारी तलवार बताया गया है, जो मिलों और आपूर्तिकर्ताओं दोनों को प्रभावित कर रहा है। मिल मालिकों ने नई सरकार से शेष भंडार जारी करने, आपातकालीन आयात की अनुमति देने और उद्योग के लिए व्यवहार्य मूल्य दायरा बहाल करने का आग्रह किया है। उन्होंने शून्य-भंडार आदेश को वापस लेने या उसकी समयसीमा बढ़ाने की भी मांग की है ताकि उपलब्ध कच्चा पटसन बाजार में आ सके। पटसन क्षेत्र में लगभग दो लाख श्रमिक कार्यरत हैं, और उद्योग को डबल इंजन सरकार से स्थिरता और सहयोग की उम्मीद है।

जीई एयरोस्पेस का पुणे संयंत्र में 100 करोड़ का नया निवेश

उत्पादन क्षमता बढ़ाने और वैश्विक आपूर्ति को मजबूत करने का लक्ष्य

नई दिल्ली ।

प्रमुख एयरोस्पेस कंपनी जीई एयरोस्पेस ने भारत में अपनी विनिर्माण क्षमता और उपस्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से पुणे स्थित अपने संयंत्र में 100 करोड़ रुपये के नए निवेश की घोषणा की है।

इस ताजा निवेश के साथ, पिछले तीन वर्षों में वाणिज्यिक विमान इंजनों के महत्वपूर्ण घटक बनाने वाले इस संयंत्र में कंपनी का कुल निवेश 510 करोड़ रुपये को पार कर जाएगा, जो देश में मेक इन इंडिया पहल के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कंपनी ने सोमवार को जारी एक बयान में बताया कि यह 100 करोड़ रुपये नई वेल्डिंग प्रौद्योगिकियों, उन्नत निरीक्षण उपकरणों, सटीक औजारों, गेज, फिक्स्चर और अतिरिक्त अवसंरचना उन्नयन पर खर्च किए जाएंगे।

इसका प्राथमिक उद्देश्य उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना, प्रक्रियाओं की सटीकता में सुधार लाना और वैश्विक ग्राहकों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले घटकों की निर्बाध आपूर्ति को सुनिश्चित करना है। जीई एयरोस्पेस के अनुसार यह नवीनतम निवेश पिछले दो वर्षों में घोषित 410 करोड़ रुपये के निवेश का पूरक है, जिससे पुणे संयंत्र में तीन साल का कुल निवेश 510 करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा। पुणे विनिर्माण संयंत्र के एक अे धिकारी ने इस कदम को भारत में विनिर्माण के प्रति कंपनी की मजबूत प्रतिबद्धता बताया।

उन्होंने कहा कि हम कौशल विकास पर भी काम कर रहे हैं, जो भारत में वैमानिकी उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन बनेगा।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कंपनी आपूर्तिकर्ताओं और कौशल विकास के माध्यम से भारत में वैमानिकी उद्योग के लिए सरकार के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। पुणे संयंत्र के पास स्थानीय स्तर पर 300 से अधिक आपूर्तिकर्ता हैं।

जबकि भारत में जीई एयरोस्पेस के कुल आपूर्तिकर्ताओं का नेटवर्क 2,200 से अधिक है। 2015 से अब तक, इस संयंत्र ने 5,000 से अधिक उत्पादन सहयोगियों को प्रशिक्षित किया है, जिससे देश में वैमानिकी विनिर्माण प्रतिभा का एक मजबूत आधार तैयार हुआ है। बेंगलुरु में जीई एयरोस्पेस का एक प्रौद्योगिकी केंद्र भी कार्यरत है।

चीन करेगा 17 अरब डॉलर सालाना अमेरिकी कृषि उत्पादों की खरीद

वॉशिंगटन ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के बाद व्हाइट हाउस ने घोषणा की है कि चीन 2026 से सालाना 17 अरब अमेरिकी डॉलर के कृषि उत्पादों की खरीद करेगा। यह कदम व्यापार युद्ध से प्रभावित अमेरिकी किसानों को बड़ी राहत देगा और द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में सुधार का संकेत है। यह समझौता 2026 से 2028 तक प्रति वर्ष 17 अरब डॉलर के स्तर पर रहेगा। इसमें अमेरिकी कृषि विभाग द्वारा बर्ड फ्लू से मुक्त घोषित किए गए राज्यों से पोल्ट्री आयात फिर से शुरू करना शामिल है। यह पिछली सोयाबीन खरीद प्रतिबद्धताओं के अतिरिक्त होगा। समझौते के तहत दोनों पक्ष एक-दूसरे की कृषि आयात संबंधी गैर-शुल्क बाधाओं और बाजार पहुंच की चिंताओं को दूर करने पर सहमत हुए हैं, जिसमें

चीनी डेयरी व समुद्री उत्पाद और अमेरिकी गोमांस प्रसंस्करण इकाइयां शामिल हैं। कुछ उत्पादों पर जवाबी शुल्क कटौती पर भी सहमति बनी है। हालांकि, चीन ने अभी तक इस समझौते की तत्काल पुष्टि नहीं की है और खाद्य सुरक्षा के मद्देनजर अपने कृषि आयात स्रोतों में विविधता लाने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है।

प्याज के आँसू: महाराष्ट्र के किसान गहरे संकट में, लागत भी निकालना मुश्किल

जंग के कारण निर्यात हुआ कम, कौड़ियों में बिक रहा प्याज

नासिक।

महाराष्ट्र के नासिक और सोलापुर जिलों से सामने आ रही तस्वीरें इसका सबूत हैं कि मुसीबत की घड़ी आ गई है। प्याज के गिरते दामों ने इन क्षेत्रों के हजारों किसानों की कमर तोड़ दी है। मंडियों में प्याज की भरमार है, लेकिन खरीदार न मिलने या बहुत कम दाम मिलने के कारण अन्नदाता परेशान हैं। उन्हें अपनी मेहनत का उचित मूल्य मिलना तो दूर, लागत भी निकालना मुश्किल हो रहा है, जिससे दिवालिया होने का खतरा मंडरा रहा है। इस सीजन में महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक बेल्ट में किसानों को भारी निराशा हाथ लगी है। पहले बेमौसम बारिश ने फसल को नुकसान पहुंचाया, और अब पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव और युद्ध के कारण प्याज का निर्यात बुरी तरह प्रभावित हो गया है। नतीजतन, थोक मंडियों में प्याज के दाम उत्पादन लागत से काफी नीचे गिर गए हैं, इससे किसानों को भारी वित्तीय घाटा हो रहा है।

नासिक, सोलापुर और छत्रपति संभाजीनगर के किसानों के कई हृदय विदारक मामले सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, पाथन तालुका के किसान ने 1,262 किलो प्याज बेचने के बाद अपने खाते में माइनस एक रुपया देखा, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इसी तरह, सताना एपीएमसी में जितेंद्र सोलंकी को 30 क्विंटल प्याज 175 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचना पड़ा, जबकि प्याज को उगाने में 1,200 रुपये प्रति क्विंटल का खर्च आया था। उन्हें सीधे तौर पर 36,000 रुपये का घाटा हुआ। पुणे के किसान बताते हैं कि वे प्याज को 4-5 रुपये प्रति किलो बेच रहे हैं, जबकि उनकी उत्पादन लागत 12 रुपये प्रति किलो से कहीं अधिक है।

वहीं देश की सबसे बड़ी प्याज मंडी, लासलगांव एपीएमसी में भी हालात गंभीर हैं। यहां भाव 400 से 1,600 रुपये प्रति क्विंटल तक हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश, करीब 80 प्रतिशत प्याज 800 रुपये प्रति क्विंटल से भी कम में बिक रहा है। सोलापुर में 13 मई को 14,756 क्विंटल प्याज की आवक हुई, लेकिन भाव 100 से 1,700 रुपये प्रति क्विंटल के बीच ही रहे। महाराष्ट्र ऑनियन ग्रोअर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के अनुसार, प्याज का ब्रेक-ईवन भाव 18 रुपये प्रति किलो है, जबकि अधिकांश किसान 4-8 रुपये प्रति

किलो में बेचने को मजबूर हैं। उन्होंने बताया कि इस बार ग्रेड-1 प्याज की मात्रा कम है और युद्ध के कारण विदेशों में मांग घटने से निर्यात में भी कमी आई है।

नीट पेपर लीक: ड्डलातूर में कोचिंग संचालक गिरफ्तार, अब तक 10 की गिरफ्तारी

सीबीआई को उम्मीद अभी कई परतें खुलनी बाकी

लातूर।

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) में कथित पेपर लीक मामले की जाँच में जुटी केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) ने अपनी कार्रवाई तेज कर सोमवार को महाराष्ट्र के लातूर से एक बड़े कोचिंग सेंटर के निदेशक शिवराज मोटेगांवकर को गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी के साथ ही हाई-प्रोफाइल मामले में अब तक कुल 10 आरोपी सलाखों के पीछे पहुँच चुके हैं। सीबीआई को संदेह है कि मोटेगांवकर के कोचिंग सेंटर रेणुकाई कैमिस्ट्री क्लासेस (आरसीसी) के माध्यम से नीट के प्रश्नपत्र लीक किए गए थे और छात्रों व स्थानीय डॉक्टरों तक पहुँचाया गया।

बात दें कि मोटेगांवकर, जो लातूर सहित सात जिलों में रेणुकाई कैमिस्ट्री क्लासेस (आरसीसी) नामक कोचिंग सेंटर चलाता है, से पहले 15 मई को उसके घर पर आठ घंटे तक पूछताछ की गई थी। इसके बाद रविवार को सीबीआई ने आरसीसी के मुख्य कार्यालय पर छापा मारकर कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। रिपोर्टों के अनुसार, इस कोचिंग सेंटर का वार्षिक टर्नओवर 100 करोड़ रुपये तक बताया जा रहा है, जो इसकी व्यापक पहुँच और क्षमता को दिखाता है। सीबीआई को शक है कि लातूर के कई रसूखदार डॉक्टरों ने भी लीक हुए प्रश्नपत्रों को मोटी रकम देकर खरीदा था, जिससे उनके बच्चों या अन्य उम्मीदवारों को अनुचित लाभ मिल सके।

जांच एजेंसी सीबीआई के मुताबिक लातूर को पूरे सिंडिकेट का महत्वपूर्ण केंद्र बताया जा रहा है, जहाँ कथित तौर पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा की पवित्रता के साथ खिलवाड़ हुआ।

लातूर, जो अपनी शैक्षिक संस्कृति और कोचिंग केंद्रों के लिए मशहूर है, अब एक बड़े घोटाले के केंद्र के रूप में उभर रहा है। सीबीआई को पुख्ता सबूत मिले हैं कि इस नेटवर्क के तार न केवल स्थानीय स्तर पर, बल्कि देश के अन्य राज्यों, विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश से भी जुड़े हुए हैं। जांच एजेंसी को शुरुआती पड़ताल में सामने आया है कि लातूर के कुछ नामी डॉक्टर उस बड़े गिरोह से जुड़े थे जो पहले से ही बिहार और उत्तर प्रदेश में सक्रिय था। इन डॉक्टरों ने कथित तौर पर छात्रों को पेपर उपलब्ध कराने और परीक्षा के दौरान सॉल्वर गैंग का इंतजाम करने में अहम भूमिका निभाई। सीबीआई अब संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की भी पड़ताल कर रही है, जो परीक्षा से ठीक पहले इन संदिग्धों के खातों में हुए थे।

यूपी में मैजिक को ट्रक ने मारी टक्कर, 10 लोगों की मौत, 3 गंभीर

लखीमपुर-खीरी।

लखीमपुर-खीरी के ईशानगर थाना क्षेत्र के उंचा गांव के पास सोमवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में 09 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की मौत अस्पताल ले जाते समय हुई। इस हादसे में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है।

सूत्रों के मुताबिक सोमवार सुबह सवारियों से भरी एक मैजिक गाड़ी लखीमपुर से सिसैया जा रही थी। गाड़ी उंचा गांव के पास पहुंची ही थी कि बहराइच की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मैजिक गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। जानकारी के मुताबिक हादसा होते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई। आस-पास के खेतों में काम कर रहे लोग और ग्रामीण मदद के लिए दौड़े। लोगों ने गाड़ी में फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश शुरू की, लेकिन तब तक आठ लोग दम तोड़ चुके थे। सूचना मिलते ही ईशानगर थाने की पुलिस बल मौके पर पहुंचा और राहत-बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ट्रक को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है।

240 चैंबरों पर चला बुलडोजर, वकीलों ने 'लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन' बताया

घटना के बाद बार एसोसिएशन और वकीलों में भारी आक्रोश, आंदोलन की दी चेतावनी

लखनऊ।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रविवार को वकीलों के अवैध चैंबरों पर चला बुलडोजर बड़ा विवाद बन गया। प्रशासन की कार्रवाई में भारी पुलिस बल तैनात रहा और विरोध कर रहे वकीलों पर लाठीचार्ज किया गया। इस घटना के बाद बार एसोसिएशन और वकीलों में भारी आक्रोश देखने को मिला। वकीलों ने इसे ÷लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन÷ बताते हुए बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट ने कुछ अवैध चैंबरों को हटाने का निर्देश दिया था, जिसके बाद नगर निगम की टीम के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचा और चैंबर तोड़ने की कार्रवाई शुरू हुई। हालांकि इस दौरान वकीलों ने विरोध भी किया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया।

वकीलों का आरोप है कि हाईकोर्ट ने केवल 72 चैंबर हटाने का आदेश दिया था, लेकिन प्रशासन ने आदेश की आड़ में करीब 240 चैंबरों पर कार्रवाई कर दी। उनका कहना है कि जिन चैंबरों को चिन्हित किया गया था, उनमें कई वकीलों के चैंबर शामिल ही नहीं थे, बावजूद इसके उन्हें भी तोड़ दिया गया।

रिपोर्ट के मुताबिक बुलडोजर कार्रवाई के दौरान कई वकीलों की तबीयत भी बिगड़ गई। कुछ वकील जमीन पर बैठकर विरोध जताते रहे तो कुछ ने कार्रवाई रोकने की मांग को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से बहस की। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। वकीलों का कहना है कि वे पिछले करीब 30 सालों से वहीं बैठकर वकालत कर रहे हैं और अचानक इस तरह की कार्रवाई उनके रोजगार पर सीधा हमला है। वकीलों ने प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर उन्हें वहां से हटाया जा रहा है तो पहले उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए थी।

शराब घोटाला मामले की सुनवाई अब जज स्वर्ण कांता नहीं जस्टिस मनोज जैन करेंगे

मंगलवार को सुनवाई शुरू होगी, अवमानना मामले की भी शुरुआत होगी

नई दिल्ली।

कथित शराब घोटाले मामला जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के बाद अब नई बेंच को ट्रांसफर किया जा चुका है। इस मामले की सुनवाई अब जस्टिस मनोज जैन करेंगे। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत छह आप नेताओं के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के बाद जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने खुद को इस मामले से अलग कर लिया था। वहीं, अवमानना केस की सुनवाई जस्टिस नवीन चावला और रविंद्र जस्टिस रविंदर दुडेजा की खंडपीठ करेगी। दोनों ही मामलों की सुनवाई मंगलवार को होगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, दिल्ली सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के अलावा दुर्गेश पाठक और विनय मिश्रा के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया था। इसके साथ ही उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए मामले को किसी और बेंच को ट्रांसफर किए जाने का ऐलान किया था। अब इस मामले को जस्टिस मनोज जैन की कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है। एक तरफ जहां मंगलवार को शराब घोटाले मामले की सुनवाई शुरू होगी तो दूसरी तरफ अवमानना मामले की भी शुरुआत होगी। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर दुडेजा की बेंच के सामने इस मामले को सूचीबद्ध किया गया है। कोर्ट केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के छह नेताओं के खिलाफ इस मामले की सुनवाई करेगी। इसके अलावा वे लोग भी दायरे में आ सकते हैं जिन्होंने यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो अपलोड किए थे जिनमें जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा पर अपमानजनक टिप्पणियां की गई थीं। इस मामले को जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत में सूचीबद्ध किया गया तो केजरीवाल ने आपत्ति जताई थी। उन्होंने चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर इस मामले को दूसरी बेंच के सामने ट्रांसफर करने की मांग की थी, लेकिन जब उन्होंने इससे इनकार कर दिया तो केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के सामने रिक्यूजल याचिका दायर करके मांग की कि वह खुद को इस मामले से अलग कर लें। केजरीवाल ने आशंका जाहिर की थी कि उन्हें जस्टिस शर्मा की अदालत में न्याय नहीं मिल सकता है। केजरीवाल ने उन पर हितों के टकराव और आरएसएस से जुड़े संगठन के कार्यक्रम में शामिल होने का आरोप लगाया था।

आजादी मिलने के बाद भी रोहनात गांव में आज भी जमीन के लिए संघर्ष कर रहे लोग

अंग्रेजों ने ग्रामीणों की भूमि कर दी थी नीलाम, तोपों से उड़ा दिया था पूरा गांव

चंडीगढ़।

हरियाणा का एक ऐसा गांव जहां आजादी के 71 साल बाद राष्ट्रीय ध्वज लहराया गया। आजादी के 71 साल बाद 23 मार्च 2018 को पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इस गांव में जाकर ध्वजारोहण किया था। दरअसल इस गांव की रूह कंपाने वाली कहानी सन 1887 की है, जब इस गांव के लोगों को अंग्रेजी हुकूमत ने बड़ी बर्बरता के साथ मौत के घाट उतार दिया था। भिवानी जिले के रोहनात गांव का इतिहास आज भी स्वतंत्रता संग्राम की उन घटनाओं की याद दिलाता है, जिसने इस क्षेत्र को खून और संघर्ष से रंग दिया था।

रिपोर्ट के मुताबिक भिवानी जिले का रोहनात गांव 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बड़ा केंद्र रहा। स्थानीय लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जमकर संघर्ष किया, जिसके बाद अंग्रेजों ने गांव पर भीषण दमन किया। जानकारी के मुताबिक उस दौर में गांव पर तोपों से हमला किया गया और कई ग्रामीणों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। बचे हुए लोगों को हांसी ले जाकर रोड रोलर से कुचलने की भी घटनाओं का जिक्र इतिहास में मिलता है। यह सड़क आज भी 'लाल सड़क' के नाम से जानी जाती है।

अंग्रेजी हुकूमत की ये बर्बरतापूर्ण घटना 29 मई 1857 की है। जब रोहनात गांव में ब्रिटिश सैनिकों ने इस दिन बर्बर खूनखराबा किया था, लेकिन रोहनात गांव के लोगों ने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। ग्रामीणों ने देसी औजारों से अंग्रेजी हुकूमत का सामना किया, लेकिन उनके हथियारों और तोपों के सामने गांव वालों की चल न सकी। अंग्रेजों ने गांव को तोपों से उड़ा दिया और कई ग्रामीणों को रोड रोलर से कुचल दिया। ब्रिटिश सैनिकों ने गांव वालों को पीने का पानी भी नहीं लेने दिया और कुंए के मुंह को मिट्टी से ढक दिया। उसके बाद लोगों को फांसी पर लटका दिया था।

इस हमले के बाद अंग्रेजों ने भी गांव पुत्ती मंगल क्षेत्र में तोपों से हमला करना शुरू किया। गांव रोहनात के सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं गांव के बिरड़ दास बैरागी को तोप पर बांध कर उनके शरीर को चीथड़ों की तरह उड़ा दिया। गांव की कई महिलाओं ने उस दौरान

अपनी इज्जत बचाने के लिए गांव के कुंए में कूद कर अपनी जान दे दी। अंग्रेजों से लोहा लेने की सजा आज भी ग्रामीण भुगत रहे हैं। अंग्रेजों ने यहां के ग्रामीणों की कृषि योग्य भूमि नीलाम कर दी थी, लेकिन अभी तक ग्रामीणों के नाम पर यह जमीन नहीं हो पाई है। भूमि नीलाम होने के बाद अंग्रेजों ने गांव में अधिकारी भेजे और उनसे इस बारे में माफी मांगने के लिए कहा लेकिन ग्रामीणों ने माफी नहीं मांगी।

लुधियाना के नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, परीक्षा के बीच हड़कंप

लुधियाना।

औद्योगिक नगरी लुधियाना में तब हड़कंप मच गया, जब तीन प्रमुख स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। यह सनसनीखेज धमकी ई-मेल के जरिए दी गई, जिससे पूरे शहर में खौफ का माहौल पैदा हुआ। दिल दहला देने वाली बात यह थी कि जिस समय यह धमकी मिली, स्कूलों में बच्चों की परीक्षाएं चल रही थीं। खबर फैलते ही स्कूलों में अफरा-तफरी मच गई और बच्चों के माता-पिता अपने काम-धंधे छोड़कर उन्हें सुरक्षित घर लाने के लिए स्कूलों की ओर दौड़ पड़े। देखते ही देखते स्कूलों के बाहर अभिभावकों की भारी भीड़ जमा हो गई। मामले की गंभीरता को देखकर लुधियाना पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला। भारी पुलिस बल, बम निरोधक दस्ते टीमें मौके पर पहुंचीं और एहतियातन तीनों स्कूलों को पूरी तरह खाली कराया गया। इसके बाद चप्पे-चप्पे की सघन तलाशी ली गई। थाना सराभा नगर के एसएचओ इंस्पेक्टर ने पुष्टि की कि व्यापक जांच के बावजूद स्कूलों के भीतर से कोई भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक बरामद नहीं हुआ है। फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। पुलिस अब साइबर सेल की मदद से इस धमकी भरे ई-मेल के स्रोत और भेजने वाले की गहन जांच कर रही है।

केरल में महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा, फ्रंटलाइन वर्कर्स का मानदेय बढ़ा

सतीशन सरकार का पहला मास्टरस्ट्रोक

तिरुवंतनमपुरम।

केरल में नवगठित यूडीएफ सरकार ने मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन के नेतृत्व में सत्ता संभालने के तुरंत बाद कई महत्वपूर्ण कल्याणकारी घोषणाएं की हैं। सोमवार को पदभार ग्रहण करने के बाद अपनी पहली कैबिनेट बैठक में, सतीशन सरकार ने 15 जून से केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) की बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का ऐलान कर दिया। यह कदम महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इन घोषणाओं में, आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में 3,000 रुपये की वृद्धि हुई है, जो उनकी टीरेलेसली सेवा को मान्यता देती है। इसके अतिरिक्त, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिकाओं और आयाओं (सहायकों) के मानदेय में भी 1,000 रुपये का इजाफा किया है। रसोइया कर्मचारियों को भी 1,000 रुपये की वृद्धि मिलेगी, जिससे विभिन्न क्षेत्रों के जमीनी स्तर के कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री सतीशन ने केरल की वित्तीय और राजकोषीय स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने की भी घोषणा की, जो सरकार की पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साथ ही, 2023 में नव केरल यात्रा के दौरान युवा कांग्रेस नेताओं पर हुए हमले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया जाएगा। इसके पहले सोमवार को, सेंट्रल स्टेडियम में एक भव्य समारोह में मुख्यमंत्री सतीशन और उनके 20 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। बाद में, सतीशन ने राज्य सचिवालय में अपने कार्यालय में विधिवत कार्यभार संभाला, जहां उन्हें बधाई देने वालों में कोच्चि के विधायक मोहम्मद शियास प्रमुख थे। नई सरकार ने अपने पहले दिन ही जनोन्मुखी और निर्णायक फैसलों से अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी हैं।

जम्मू-कश्मीर में बढ़ा ड्रग्स कारोबार, 13प्रतिशत आबादी नशे की चपेट में

पंजाब और सीमा पार से पहुंच रही नशीले पदार्थों की खेप
सरकार ने शुरू किया 100 दिन का विशेष अभियान

श्रीनगर।

जम्मू और कश्मीर में नशे के कारोबार की समस्या तेजी से गंभीर होती जा रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेश की लगभग 1.3 करोड़ आबादी में से करीब 13.5 लाख लोग किसी न किसी रूप में ड्रग्स की चपेट में हैं। यह कुल आबादी का 13 प्रतिशत से अधिक है। वर्ष 2022 में यह संख्या लगभग 6 लाख बताई गई थी, जिससे स्पष्ट है कि पिछले कुछ वर्षों में नशे की समस्या में चिंताजनक वृद्धि हुई है।अधिकारियों का कहना है कि आतंकवाद के साथ-साथ अब ड्रग्स नेटवर्क भी जम्मू-कश्मीर के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। विशेषज्ञ पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और नशीले पदार्थों की तस्करी को क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बता रहे हैं। इसी को देखते हुए प्रशासन ने 100 दिन का विशेष नशा-विरोधी अभियान शुरू किया है, जिसमें अब तक एक करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। दक्षिण कश्मीर के रहवासी बताते हैं, कि जिनके बच्चे पहले पढ़-लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर और वकील बनना चाहते थे, लेकिन अब वही स्कूल में सिगरेट की आदत लगने के बाद वह धीरे-धीरे चरस और हेरोइन जैसी खतरनाक ड्रग्स की गिरफ्त में आने लग गए हैं। हालत यह हो गई कि नशे की लत पूरी करने के लिए ऐसे बच्चे घर का सामान तक बेचना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ जिन्होंने नशे की लत को छोड़ वापस सामाजिक जीवन में आ गए हैं तो इस कारोबार के पीछे संगठित गिरोह के सक्रिय होने की बात कहते हैं, जिनके संबंध पंजाब के ड्रग्स तस्करों से जुड़े होना बताया जा रहा हैं। सीमावर्ती इलाकों के जरिए नशीले पदार्थ जम्मू-कश्मीर तक पहुंचाए जा रहे हैं।

165 हॉटस्पॉट चिन्हित

ड्रग्स नेटवर्क पर कार्रवाई तेज करते हुए प्रशासन ने अब तक 165 हॉटस्पॉट चिन्हित किए हैं, जहां नशे का कारोबार अधिक सक्रिय है। एनडीपीएस एक्ट के तहत 704 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 830 से ज्यादा नशेड़ियों व ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। सरकार ने पहली बार सख्त नीति अपनाते हुए ड्रग्स कारोबार में शामिल लोगों के आधार कार्ड, पासपोर्ट, हथियार लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान संबंधी दस्तावेज रद्द करने शुरू कर दिए हैं। अब तक 300 ड्राइविंग लाइसेंस और 130 वाहनों के रजिस्ट्रेशन निरस्त किए जा चुके हैं। इसके अलावा 110 मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, जबकि दो दुकानों के लाइसेंस पूरी तरह रद्द कर दिए गए हैं।

भारत में 28 मई को मनाई जाएगी ईद-उल-अजहा, शाही इमाम ने किया ऐलान

नई दिल्ली।

देशभर में मुसलमानों के दूसरे सबसे बड़े त्योहार बकरीद (ईद-उल-अजहा) की तारीख का ऐलान हो गया है। दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद के शाही इमाम सैय्यद शाबान बुखारी ने ऐलान किया है कि भारत में इस साल बकरीद गुरुवार 28 मई को मनाई जाएगी। जामा मस्जिद दिल्ली में मर्कज़ी रुयत-ए-हिलाल कमेटी के इजलास के बाद वीडियो संदेश जारी करते हुए शाही इमाम सैय्यद शाबान बुखारी ने कहा कि जिलहिज्ज का चांद नजर नहीं आया। मर्कज़ी रुयत-ए-हिलाल कमेटी जामा मस्जिद दिल्ली के इजलास में 30 की रुयत का फैसला किया। उन्होंने ऐलान किया कि चूंकि चांद नजर नहीं आया है, इसलिए इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी महीने जिलहिज्ज की पहली तारीख 19 मई 2026 दिन मंगलवार को होगी। इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक बकरीद का त्योहार जिलहिज्ज महीने की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। शाही इमाम ने साफ किया कि जिलहिज्ज का महीना 19 मई से शुरू हो रहा है, इस लिहाज से 10 जिलहिज्ज 28 मई को पड़ेगी। उन्होंने कहा कि ईद-उल-अजहा इंशाअल्लाह 28 मई गुरुवार के रोज़ होगी। इस ऐलान के साथ ही देश भर में बकरीद की तैयारियों को लेकर स्थिति साफ हो गई है।

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक कजोड़मल मीना के लिए स्काईटक प्रिन्टर्स, 111, नवाब कल्लन का बाग, एमएलए क्वार्टर, नीयर समाचार जगत, एमआई रोड, जयपुर से मुद्रित एवं 303, भव्य टॉवर, कबीर मार्ग, बनीपार्क जयपुर से प्रकाशित।
(इस अंक में प्रकाशित समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पीआरबी एक्ट के तहत उत्तरदायी) समस्त विवादों का न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर शहर होगा। RNI No. RAJHIN/2001/05699 मो. नं. 9928078717